भारतीय शेयर बाजार हुआ पस्त

ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने और शांति समझौते की उम्मीद धुंधली पड़ने से 91 डॉलर के पार पहुंचा ब्रेंट

मुंबई, 18 अगस्त पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने का असर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों की चिंता बढ़ी और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 365 अंक तक टूट गया. निफ्टी भी 76 अंक नीचे आ गया.

बाजार में सबसे ज्यादा दबाव आईटी शेयरों पर रहा, जबकि ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग शेयरों ने मामूली मजबूती दिखाई.सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 365 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,362 अंक पर आ गया. वहीं निफ्टी 76 अंक यानी 0.31 प्रतिशत फिसलकर 24,211 अंक पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले सोमवार को भी दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही थी. निफ्टी की लगातार गिरावट ने बाजार धारणा पर दबाव और बढ़ा दिया है. बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रही. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने तथा युद्धविराम को आगे बढ़ाने की संभावना कमजोर होने से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. अमेरिकी डब्ल्यूटीआई भी एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 85.37 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया.

> हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और भारतीय कंपनियों की आय में सुधार के संकेत बाजार को कुछ सहारा दे सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की स्थिति, कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे.कुल मिलाकर, जब तक पश्चिम एशिया तनाव कम नहीं होता और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी नहीं आती, भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका है.

ओएसएम ने इलेक्ट्रा एआई से साझेदारी की

नयी दिल्ली, 18 अगस्त इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली भारतीय कंपनी ओमेगा सीकी मोबिलिटी (ओएसएम) ने मंगलवार को इलेक्ट्रा एआई के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की. इस साझेदारी के तहत ओएसएम के इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र में उन्नत बैटरी हेल्थ इंटेलिजेंस को एकीकृत किया जायेगा जिसमें इलेक्ट्रा एआई को महारथ है. यह सहयोग ओएसएम के पूरे वाहन बेड़े में बैटरी पर रियल-टाइम में बैटरी की निगरानी, उत्पादक आदि उपलब्ध करायेगा. इससे वाहन प्रदर्शन में सुधार, बैटरी लाइफ को अधिकतम करने तथा ग्राहकों, वित्तीय संस्थानों, खुदरा दुकानदारों और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

भारत-जर्मनी से 90 हजार करोड़ की पनडुब्बी डील

8 अरब यूरो की डील पर जल्द हो सकता है समझौता

भारत में ही बनेंगी छह अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां

नई दिल्ली, 18 अगस्त भारत और जर्मनी के बीच भारतीय नौसेना के लिए छह अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर करीब 8 अरब यूरो यानी 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का समझौता जल्द होने की उम्मीद है.

जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन के अनुसार, दोनों देश इस महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. प्रस्तावित परियोजना के तहत पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा क्षमता के साथ-साथ घरेलू रक्षा विनिर्माण को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना-75आई के तहत जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के बीच समझौता होने की संभावना है. यह परियोजना भारतीय नौसेना के पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.प्रस्तावित पनडुब्बियों में वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली लगाए जाने की उम्मीद है. इस तकनीक की मदद से पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं. इनमें आधुनिक सेंसर, टॉरपीडो, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भी शामिल की जा सकती हैं.

> भारत के लिए यह सौदा ऐसे समय में अहम है जब भारतीय नौसेना पारंपरिक पनडुब्बियों की कमी का सामना कर रही है. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक और पनडुब्बी गतिविधियां बढ़ने के बीच भारत अपनी समुद्री निगरानी और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है.प्रस्तावित छह पनडुब्बियों के भारत में निर्माण से घरेलू रक्षा उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है.

निर्यातकों से बढ़ सकते हैं ओरिजिन के दस्तावेज

40 से ज्यादा देशों के जरिये चीनी माल भेजने का दावा

भारत की किसी कंपनी या शिपमेंट का नाम नहीं

नई दिल्ली, 18 अगस्त अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर चल रही बातचीत के बीच व्हाइट हाउस की एक नई रिपोर्ट में भारत का नाम चीन के सामान की कथित ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले देशों में किया गया है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से आने वाले कुछ उत्पाद अमेरिका में ऊंचे टैरिफ से बचने के लिए भारत समेत 40 से अधिक देशों के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुंच रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट में किसी भारतीय कंपनी, फैक्ट्री या किसी खास शिपमेंट को नियमों के उल्लंघन का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है.व्हाइट हाउस की 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम: राइज, स्कोप एंड कॉस्ट्स' रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कुछ चीनी उत्पादों को पहले ऐसे देशों में भेजा जाता है जहां अमेरिकी शुल्क अपेक्षाकृत कम हैं. वहां उनकी पैकेजिंग, लेबल या दस्तावेज बदले जाते हैं अथवा सीमित स्तर पर प्रोसेसिंग की जाती है. इसके बाद इन्हें उस देश के उत्पाद के तौर पर अमेरिका भेजे जाने का दावा किया गया है. रिपोर्ट में भारत के साथ वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों का भी उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में करीब 67 अरब डॉलर का चीनी सामान इस तरह अमेरिकी बाजार में पहुंचा हो सकता है.

मधुमक्खी पालन पर हरियाणा देगा 85 प्रतिशत सब्सिडी

नई दिल्ली, 18 अगस्त. किसानों की आमदनी बढ़ाने और मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार 75 से 85 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है.

राज्य के उद्यान विभाग की इस पहल के तहत मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनी और जरूरी उपकरण खरीदने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का जोर पारंपरिक खेती के साथ किसानों को 'स्वीट रिवोल्यूशन' से जोड़ने पर है, ताकि उन्हें खेती के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिल सके. मधुमक्खी पालन की खासियत यह है कि इसके लिए किसानों को अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ती.

300 रुपए में एक साल तक रिचार्ज महंगा होने की चिंता खत्म

प्लान बदलने की भी आजादी, प्रीपेड-पोस्टपेड और नए ग्राहक सभी ले सकेंगे प्राइम

मुंबई, 18 अगस्त मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं तो जियो प्राइम ग्राहकों को एक साल की कीमत की गारंटी देगा. 300रुपए की एकमुश्त सदस्यता लेकर ग्राहक अपने मौजूदा जियो प्लान की आज की कीमत 5 सितंबर 2027 तक लॉक कर सकेंगे. यानी प्राइम सदस्य अपने प्लान को पूरे सदस्यता काल में मौजूदा कीमत पर ही रिचार्ज कर पाएंगे.

अच्छी बात यह है कि प्राइम लेने के बाद ग्राहक किसी एक प्लान में बंधे नहीं रहेंगे. वे चाहें तो दूसरे जियो प्लान से भी रिचार्ज कर सकते हैं और प्राइम सदस्यता के फायदा उठा सकते हैं.

जियो प्राइम 20 अगस्त से उपलब्ध होगा. ग्राहक ऐप, , जियो स्टोर्स या अधिकृत जियो पार्टनर स्टोर्स से सदस्यता ले सकेंगे. प्राइम मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के साथ नए जियो ग्राहकों के लिए भी खुला है.

दूसरे नेटवर्क के ग्राहक नंबर पोर्ट कराकर या नया जियो कनेक्शन लेकर इसमें शामिल हो सकते हैं.जियो प्राइम ऐसे समय आया है जब टेलीकॉम बाजार में रिचार्ज की कीमतें फिर चर्चा में हैं.

एयरटेल ने हाल में अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए 299रुपए समेत कुछ लोकप्रिय प्लान हटा दिए हैं. इसके बाद 28 दिन की डेली-डेटा श्रेणी में 349 रुपए वाला प्लान शुरुआती विकल्प बन गया है. दूसरी तरफ जियो ने साफ किया है कि उसका मौजूदा 299 रुपए वाला प्लान जारी रहेगा.

> प्राइम कोई नया अनिवार्य रिचार्ज प्लान नहीं है. प्राइम सदस्यता के साथ कुल 600 रुपए के दो कैशबैक वाउचर भी मिलेंगे. इनमें 300 रुपए का एक वाउचर नया जियोहोम या जियो कनेक्शन लेने और दूसरा 300रुपए का वाउचर परिवार या दोस्त के लिए नया जियो सिम लेने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. सदस्यों को नए जियो प्रोडक्ट्स और सेवाओं का अर्ली एक्सेस तथा अलग चैनल के जरिए प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा.

ऐसे माहौल में प्राइम के जरिए एक साल के लिए मौजूदा कीमत लॉक करने का विकल्प ग्राहकों के लिए खास मायने रखता है.

कागज उद्योग के मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद

नई दिल्ली, 18 अगस्त कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार से लिखाई और छपाई के कागज उद्योग के लिए चालू वित्त वर्ष 2026-27 बेहतर रहने की उम्मीद है. कंपनी क्रिसिल के मुताबिक, हार्डवुड की आपूर्ति बढ़ने से कागज निर्माताओं की लागत में कमी आएगी, जिससे उद्योग के परिचालन मुनाफे में करीब 150 आधार अंक यानी 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. महामारी के बाद लगाए गए हार्डवुड के बागान अब कटाई के लिए तैयार हो रहे हैं, जिससे उद्योग को जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.

405 रक्षा उत्पाद अब भारत में बनेंगे

रक्षा कंपनियों के शेयरों में आठ फीसदी तक उछाल

रक्षा आयात घटेगा, घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 18 अगस्त भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 405 महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादों को शामिल किया है.

इन उत्पादों का निर्माण अब देश में ही करने पर जोर दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए करीब 3,070 करोड़ रुपये के कारोबार का अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

सूची जारी होने के बाद मंगलवार को रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों के शेयरों में भी तेज उछाल देखने को मिला.

> नई सूची में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 389 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 16 उत्पाद शामिल किए गए हैं. इनमें रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे, छोटे तंत्र, अतिरिक्त पुर्जे, घटक और कच्चा माल शामिल हैं. सूची में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर, सुखोई-30 एमकेआई और हल्के लड़ाकू विमान जैसे प्रमुख विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े उत्पाद भी शामिल हैं.

15 साल बाद पीपीएफ न निकालें, बढ़ाएं पैसा

नई दिल्ली, 18 अगस्त पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता 15 साल पूरे होने के बाद मैच्योर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निवेशक को तुरंत पूरा पैसा निकालना ही होगा. सुरक्षित निवेश और लंबे समय में टैक्स लाभ चाहने वाले निवेशकों के लिए मैच्योरिटी के बाद भी खाते को जारी रखने का विकल्प मौजूद है. पीपीएफ को पांच-पांच साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है और निवेशक अपनी जरूरत के मुताबिक तय कर सकता है कि उसे आगे भी पैसा जमा करना है या केवल मौजूदा रकम पर ब्याज लेते रहना है.

50% टैरिफ पर अमेरिका को डब्लूटीओ में घेरा

अमेरिका को भारत का क्वार्ट्ज निर्यात 380 मिलियन डॉलर

15 अगस्त से चार साल के लिए लागू हुआ टैरिफ

नई दिल्ली, 18 अगस्त अमेरिका की ओर से भारतीय क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी तक टैरिफ-रेट कोटा के खिलाफ भारत ने विश्व व्यापार संगठन का रुख किया है. भारत ने डब्लूटीओ के सेफगार्ड समझौते के तहत अमेरिका से औपचारिक परामर्श की मांग की है.

अमेरिकी शुल्क से भारतीय क्वार्ट्ज स्टोन, स्टोन स्लैब और टाइल्स के निर्यातकों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अमेरिका को करीब 380 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,100 करोड़ रुपये के क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादों का निर्यात किया था. भारत ने डब्लूटीओ को बताया है कि इस मामले में उसका 'पर्याप्त और सीधा हित' जुड़ा हुआ है. अमेरिका ने क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादों के आयात से अपने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंका जताते हुए यह सुरक्षा उपाय लागू किया है. अमेरिकी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 15 अगस्त से प्रभावी हुई है और अगले चार वर्षों तक लागू रहने वाली है. क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादों को इंजीनियर्ड स्टोन भी कहा जाता है. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से किचन काउंटर, बाथरूम वैनिटी, टेबल और अन्य निर्माण कार्यों में किया जाता है.

समाचार विशेष

यूपी में लोध समाज की कितनी ताकत?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. अभी से सियासी दांव-पेच और शह-मात का खेल शुरू हो गया है. सत्ता में आने के लिए विपक्ष की छटपटाहट दिख रही है, तो भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है. सीएम योगी लगातार पसीने बहा रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं.

चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस हो या फिर छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हों सभी अपने वोट बैंक से आगे नए सामाजिक समीकरणों को साधने की जुगत में हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी चीफ ने उस समाज साधने की कोशिश की, जो यूपी की सत्ता की दिशा और दशा तय करता है. अखिलेश 2027 के यूपी महासमर को फतह करने के लिए लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले का विस्तार कर रहे हैं.

दरअसल, रविवार को कासगंज में स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने चुनावी वादा किया. उन्होंने मंच से कहा, 'मैं लोधी समाज के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्हें राजनीतिक सम्मान और स्थान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे.

आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग घोषित करेंगे.' अखिलेश ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 में लोधी समाज के बिना यूपी में बदलाव संभव नहीं है.

> **क्या 2027 के लिए गेम चेंजर साबित होगा यह दांव?**
>
> सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के चुनावी गणित में लोध समाज की वास्तविक ताकत कितनी है? और क्या यह अखिलेश यादव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों और जमीनी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों की 90 से 100 विधानसभा सीटों पर लोध समाज की भारी बहुलता है और वे चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि इस लोध वोट बैंक का 90 से 95 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दौर से ही यह समाज भाजपा का कट्टर और वैचारिक समर्थक माना जाता है.

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव

संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल, 8 प्रकोष्ठों में नई टीम घोषित

जयपुर. राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर नियुक्तियों का सिलसिला जारी है. निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों को सक्रिय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार पार्टी के 8 प्रमुख प्रकोष्ठों में प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. इनमें विधि, व्यावसायिक, आर्थिक, चिकित्सा, पूर्व सैनिक, खेल, विशेष संपर्क और प्रवासी प्रकोष्ठ शामिल हैं. पार्टी की ओर से 15 अगस्त को जारी सूची में प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक प्रदेश संयोजक और चार से पांच सह-संयोजकों की जिम्मेदारी तय की गई है.

विधि प्रकोष्ठ में जयपुर के सौरभ सारस्वत को प्रदेश संयोजक बनाया गया है. वहीं अलवर के शिवलाल भीणा, जयपुर के भवानी सिंह राजावत, उदयपुर के महेंद्र नागदा और बीकानेर की सुमन कंवर को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है. व्यावसायिक प्रकोष्ठ में बीकानेर के सुनील झंवर को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. बालोतरा के रमेश मसाली, झुंझुनूं के सायर सिंह, उदयपुर के शरद बंसल और जयपुर की नीता दुधरा सह-संयोजक बनाई गई है. आर्थिक प्रकोष्ठ में सिरोही के उत्तम प्रकाश अग्रवाल प्रदेश संयोजक होंगे. जयपुर के डॉ. राजा भोज शर्मा, अनिल अग्रवाल और श्रुति गुप्ता तथा पाली के राजेश दवे को सह-संयोजक बनाया गया है.

> **चिकित्सा और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में भी जिम्मेदारी**
>
> चिकित्सा प्रकोष्ठ में भीलवाड़ा के डॉ. राजा साध वैष्णव को संयोजक बनाया गया है. बीकानेर के डॉ. सिद्धार्थ असवाल, डीग के डॉ. सचिन जैन, जयपुर के कमलेश राठौड़ और पाली के डॉ. अमित राजपुरोहित सह-संयोजक होंगे. पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में जोधपुर के मेजर घनश्याम सिंह को संयोजक बनाया गया है. झुंझुनूं के रिटायर्ड कर्नल देव आनंद लोमरोड़, सीकर के कमांडर बनवारी लाल चौधरी, झुंझुनूं के विकास मालोटिया और सीकर की कविता सामोता को सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली है.

भाजपा के कांग्रेस नेता परेशान

चंडीगढ़. यह पूरे देश में हो रहा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए नेता और भाजपा के पुराने नेता आपस में लड़ रहे हैं. कई राज्यों में खुल कर विवाद सामने आ गया है और कई राज्यों में यह अभी दबा हुआ है.

हरियाणा में यह झगड़ा पिछले दिनों खुल कर दिखाई दिया. कांग्रेस से भाजपा में गए राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जहां हो रहा है वहां के स्थानीय नेताओं को बुलाना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए. यह बात उन्होंने सीधे प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को लक्ष्य करके कही. सोचें, यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का था. इस मामले में विवाद इतना बढ़ा कि उनसे माइक ले लिया गया.

इस घटना के दो दिन बाद कांग्रेस से भाजपा में गए एक दूसरे नेता कुलदीप बिश्नोई ने उठाया. उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन किया और कहा कि भाजपा को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बराबर महत्व मिलना चाहिए. ध्यान रहे राव इंद्रजीत खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनकी बेटी आरती राव हरियाणा सरकार में मंत्री है.

विशेष | कांग्रेस फिर बनाएगी बोर्ड या भाजपा करेगी वापसी?

निकाय चुनाव की आहट से गरमाई सियासत

बांसवाड़ा. नगर निकाय चुनावों की तारीखों का एलान नहीं हुआ है, किंतु सभापति का पद आरक्षित होने के बाद बांसवाड़ा शहर में चुनावी चर्चाएं परवान चढ़ रही हैं. इसमें भी बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या बांसवाड़ा नगर परिषद में कांग्रेस लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करेगी या भाजपा फिर अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी? इस बार कुछ वार्डों में भारत आदिवासी पार्टी के भी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है.

बांसवाड़ा नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं. पिछली बार 2019 में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया था. 60 में से कांग्रेस के 36 पार्षदों ने जीत हासिल की थी. वहीं, भाजपा को 21 वार्डों में जीत मिली थी, जबकि तीन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे थे. वर्ष 2024 में कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं हुए और राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी थी.

छह में से चार चुनाव में भाजपा ने बनाया बोर्ड- वर्ष 1986 के बाद बांसवाड़ा में 1994 में चुनाव हुए. इसके बाद अब तक हुए छह चुनावों में से चार बार भाजपा ने अपना बोर्ड बनाया है. 1994 से 2010-11 तक बांसवाड़ा में नगर पालिका रही. इसके बाद राज्य सरकार ने पालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद का दर्जा दिया. 1994 में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिसमें मणिलाल बोहरा नगरपालिका अध्यक्ष बने. इसके बाद 1999 में उमेश पटियात और 2004 में कृष्णा कटारा ने नगरपालिका अध्यक्ष का दायित्व संभाला. इसके बाद 2014 में मंजूबाला पुरोहित सभापति बनीं.

कांग्रेस को दो बार मिला बोर्ड बनाने का मौका- 2009 में बांसवाड़ा नगरपालिका में जनता ने पहली बार अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले. अध्यक्ष के लिए हुए सीधे चुनाव में कांग्रेस के राजेश टेलर विजयी रहे. बोर्ड भी कांग्रेस का बना. इसके बाद पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने दूसरी बार बोर्ड पर कब्जा जमाया. अब फिर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है.

> **बाप बिगाड़ सकती है समीकरण**
>
> इस बार निकाय चुनाव में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है. विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल वार्डों से भारत आदिवासी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. इससे इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है और भाजपा-कांग्रेस इसी अनुरूप रणनीति बनाने में जुटी हैं. हालांकि, अल्पसंख्यक बहुल वार्डों में कांग्रेस को पहले सफलता मिली थी. ऐसे में संभावित त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए कांग्रेस अधिक सजग नजर आ रही है.